



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रारंभिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई विस्त्री, शनिवार, अप्रैल 23, 1977/ बैंशाल 3, 1899

No. 172] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा या सख्त।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 23rd April 1977

S.O. 298(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S.O. 250(E)/18FB/IDRA/73, dated the 26th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to the liabilities relating to the banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as M/s. Hindustan Tractors Limited, Vadodara (formerly Baroda) or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of the said Order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And whereas by the Orders of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 261(E)/18FB/IDRA/74, dated the 24th April, 1974, in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development No. S.O. 173(E)/18FB/IDRA/75, dated the 9th April, 1975 and No. S.O. 309(E)/18FB/IDRA/76, dated the 22nd April, 1976 the said Order was extended for the period upto and inclusive of the 25th of April, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 11th of March, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 11th of March, 1978.

[No. F 4/1/78-CUC.]

A.K. GHOSH, Addl. Secy.

### उद्योग मंत्रालय

(श्रीयोगिक विकास विभाग)

प्रावेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1977

का० आ० 298(अ) / 18 एफ० बी० 'आई० डी० आर० ए० 8/77 —भारत सरकार के भूतपूर्व श्रीयोगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 250(अ) / 1 एफ० बी० 'आई० डी० आर० ए० 73, तारीख 26 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 1 अ० अ० की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा को थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पद्धति, करार, समझौते, पंचाट, स्वायी आदेश या अन्य लिखतें (जो दौँकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्ध दायित्वों से भिन्न हैं) जिसमें मेसर्स हिन्स्टुस्टान ट्रैक्टर्स लिं. बड़े बरा (पूर्विक बड़ोदा) नामक श्रीयोगिक उपकरण या ऐसे उपकरण की स्वारी कोई कम्पनी एक पक्ष कार है या जो ऐसे उपकरण या कम्पनी पर लाग है उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन उपगत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे।

श्रीर भारत सरकार के भूतपूर्व श्रीयोगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 261(अ) 18 एफ० बी० 'आई० डी० आर० ए०/74, तारीख 24 अप्रैल, 1974 और भूतपूर्व उद्योग और नागरिकपूर्ति मन्त्रालय (श्रीयोगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 173(अ) 18 आई० डी० आर० ए० 75, तारीख 9 अप्रैल, 1975 और सं० का० आ० 309(अ) 18 एफ० बी० 'आई० डी० आर० ए० 76, तारीख 22 अप्रैल, 1976 द्वारा, उक्त आदेश, 25 अप्रैल, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 11 मार्च, 1978 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जाए।

प्रतः, भ्रष्ट, केन्द्रीय सरकार, उच्चोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 18 वर्ष की उपद्वारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भारत की प्रवधि को 11 मार्च, 1978 तक की ओर प्रवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[सं० एफ० 4/1/73-सी० य० सी०]  
प्र० कु० खोल, अपर सचिव ।

#### ERRATUM

In the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Order No. F. 13(25)/LP/74, dated the 14th February, 1977, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 14th February, 1977, under Issue No. 68 and S.O. 162(E) on page 507, the following correction is to be made in the English version:—

In the sixth line of the said order for the word "case" read the word "cess".

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977 वैशाख 3, 1899

No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है तिससे इस भाग अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April 1977

S.O. 299(E).—Whereas in pursuance of Resolution of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. V 17020/25/77-ME(PG), dated the 23rd April, 1977, a Commission has been set up to inquire into and report on various matters as set out in the terms of reference specified in the said Resolution,

And whereas the Central Government is of opinion that all the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Act shall apply to the said Commission

[No. V.17020/25/77-ME(PG)]

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

